पीएम-स्वनिधि योजना से कारोबार में लाभ

औसत वार्षिक व्यापार लाभ में करीब 20% की वृद्धि

डिजिटल भुगतान अपनाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी

नई दिल्ली, 24 जुलाई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) योजना देशभर के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है.

योजना के जरिए न केवल लाखों छोटे कारोबारियों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, बल्कि उनके व्यापार, आय और जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. आवासन एवं

शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, योजना का दायरा अब चरणबद्ध तरीके से शहरी क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर जनगणना वाले कस्बों और शहरी बाहरी इलाकों तक विस्तारित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पात्र स्ट्रीट वेंडर्स इसका लाभ उठा सकें.

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2023 और 2025 में किए गए स्वतंत्र अध्ययनों से योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. वर्ष 2023 के अध्ययन में देश के 100 शहरी स्थानीय निकायों के 5,000 से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया था.

अध्ययन में पाया गया कि 95 प्रतिशत लाभार्थियों के लिए पीएम-स्वनिधि के तहत मिला ऋण उनका पहला बैंक ऋण था, जिसका उपयोग उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने और आय में वृद्धि के लिए किया. वर्ष 2025 में 99 शहरी स्थानीय निकायों के 5,000 से अधिक लाभार्थियों पर किए गए अध्ययन में यह सामने आया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच लाभार्थियों के औसत वार्षिक व्यापार लाभ में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

> मंत्रालय के अनुसार, ऋण उपलब्ध होने से लाभार्थी परिवारों की आय और खर्च में स्थिरता आई है, जिससे बेहतर भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. सरकार ने दूसरी ऋण किश्त सफलतापूर्वक चुका चुके लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी शुरू की है.

यह इस बात का संकेत है कि योजना केवल ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

आईटीआर भरने की समय सीमा करीब

नई दिल्ली, 24 जुलाई वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ गई है. आम करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 22 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग अपना आईटीआर जमा कर चुके हैं. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके पास अब सीमित समय बचा है. कई लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी सालाना आय आयकर सीमा से कम है तो उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है. लेकिन टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, कम आय होने के बावजूद आयकर रिटर्न दाखिल करना फायदेमंद होता है. आईटीआर आपकी आय का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है,

टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार के बड़े अवसर

अगले 10 वर्षों में 1.4 करोड़ नए कुशल कर्मचारियों की होगी जरूरत

नई दिल्ली, 24 जुलाई भारत का टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग आने वाले वर्षों में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है. उद्योग जगत और सरकार के अनुमानों के अनुसार, घरेलू मांग, निर्यात में तेजी और वैश्विक बाजार में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अगले 10 वर्षों में इस क्षेत्र को लगभग 1.4 करोड़ अतिरिक्त कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी.

वर्तमान में यह उद्योग करीब 4.6 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करा रहा है, जबकि वर्ष 2030 तक रोजगार का आंकड़ा 6 करोड़ तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते उद्योग की जरूरतों के अनुरूप

कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत किया गया, तो भारत वैश्विक टेक्सटाइल और परिधान उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन सकता है. यह जानकारी अपैरल, मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में सामने आई, जिसमें उद्योग प्रतिनिधियों, निर्यातकों, निर्माताओं, प्रशिक्षण संस्थानों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया.

गुरुवार को जारी रिपोर्ट में उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया गया कि 2030 तक भारत का अपैरल बाजार 130 से 150 अरब डॉलर के बीच पहुंच सकता है.

> हाल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, विशेषकर भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते, से भारतीय निर्माताओं को नए निर्यात बाजार मिलेंगे और कुशल कर्मचारियों की मांग में तेज वृद्धि होगी. वहीं, एएमएचएसएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि स्किल गैप स्टडी और उद्योग से लगातार संवाद के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित, उत्पादक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल उपलब्ध कराया जा सके.

कच्चा तेल 100 डॉलर के पार

मुंबई, 24 जुलाई कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर भारी दबाव देखने को मिला. कारोबार की शुरुआत से ही निवेशकों में बिकवाली का माहौल रहा, जिससे सेंसेक्स करीब 700 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ 23,666 के आसपास खुला.

वहीं, बैंक निफ्टी भी करीब 422 अंक कमजोर होकर कारोबार करता दिखा. वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता, कच्चे तेल की महंगाई और निवेशकों की सतर्कता ने घरद्धेलू बाजार की धारणा को कमजोर किया. एशियाई बाजारों का रुख भी मिला-जुला रहा. जापान का निक्केई करीब 2.83 प्रतिशत तक लुढ़क गया, जबकि हैंगसेंग में हल्की बढ़त दर्ज की गई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर महंगाई और चालू खाते के घाटे का दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. निफ्टी-50 के प्रदर्शन पर नजर डालें तो 50 में से 45 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि केवल 5 शेयरों में बढ़त दर्ज हुई. गिरते बाजार में सिप्ला, एचसीएल टेक, टीसीएस, अदाणी एंटरप्राइजेज और कोल इंडिया ने मजबूती दिखाई.

अमेरिका का 60 देशों पर नया टैरिफ लागू

नई व्यवस्था अमेरिका के 99.4% आयात व्यापार को कवर करेगी

निर्यात पर फिलहाल नहीं बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ

नई दिल्ली, 24 जुलाई अमेरिका ने भारत सहित दुनिया के 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के लिए नई टैरिफ व्यवस्था लागू कर दी है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के अनुसार, शुक्रवार से प्रभावी हुई इस व्यवस्था के तहत भारत को 10 प्रतिशत टैरिफ वाली श्रेणी में रखा गया है, जबकि कुछ अन्य देशों पर 12.5 प्रतिशत तक शुल्क लगाया गया है.

यह नई व्यवस्था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्ष की शुरुआत में लागू किए गए 10 प्रतिशत अस्थायी टैरिफ की

अवधि समाप्त होने के बाद लागू हुई है. सरकार और व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि यह व्यवस्था पुराने शुल्क का स्थान ले रही है, इसलिए भारतीय निर्यातकों पर फिलहाल कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा अमेरिका ने यह कदम फोर्स्ड लेबर (बंधुआ मजदूरी) से जुड़े आयात के मुद्दे पर धारा 301 के तहत उठाया है.

नई टैरिफ व्यवस्था अमेरिका के कुल आयात व्यापार के लगभग 99.4 प्रतिशत हिस्से को कवर करेगी. यूएसटीआर ने पिछले महीने इस संबंध में 10 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव जारी किया था, जिसके बाद समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने पर अब नई दरें लागू कर दी गई हैं.

भारत के लिए राहत की बात यह है कि उसे न्यूनतम 10 प्रतिशत टैरिफ वाली श्रेणी में रखा गया है.

दो दिन में 4,400 सस्ता हुआ सोना, चांदी 9,600 लुढ़की

नई दिल्ली, 24 जुलाई सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले दो कारोबारी सत्रों में सोना करीब 4,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 9,600 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ब्रेंट क्रूड के 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने से महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ी है, जिसका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है. वायदा बाजार में अगस्त डिलीवरी वाला सोना गिरकर 1,41,742 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जबकि सितंबर डिलीवरी की चांदी शुरुआती कारोबार में 2,17,325 रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसल गई.

आईपीओ पर टूटा निवेशकों का भरोसा

नई दिल्ली, 24 जुलाई आईटी समाधान उपलब्ध कराने वाली एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है.

ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में करीब आधी गिरावट आने के बावजूद दूसरे दिन भी निवेशकों का उत्साह कम नहीं हुआ. शुक्रवार सुबह 11 बजे तक यह आईपीओ 1.43 गुना सब्सक्राइब हो चुका था. कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 166.80 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. निवेशक 27 जुलाई तक इस इश्यू में आवेदन कर सकते हैं. शेयरों का आवंटन 28 जुलाई को होगा, जबकि 30 जुलाई को शेयरों की शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना है.

सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा निवेशकों ने सबसे अधिक रुचि दिखाई है. खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 1.80 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.25 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) का कोटा 0.91 गुना सब्सक्राइब हुआ.

एयरलाइंस शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं : अडानी

नयी दिल्ली, 24 जुलाई हवाई अड्डा निर्माण और परिचालन समेत विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले अडानी समूह ने मीडिया में आई रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि विमान सेवा कंपनी शुरू करने का 'कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है'.

समूह के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को जारी बयान में इन मीडिया रिपोर्टों को आधारहीन और तथ्यों से परे बताया.

उल्लेखनीय है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक देश में कोई भी हवाई अड्डा परिचालक किसी

विमान सेवा कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकता है. मीडिया में पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार बाजार पर एक या दो एयरलाइंस का आधिपत्य समाप्त कर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहती है और इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है ताकि हवाई अड्डा संचालकों को भी एयरलाइंस शुरू करने का अधिकार मिल सके. इसमें कहा गया था कि अडानी समूह और जीएमआर को इसका फायदा मिल सकता है जो देश के दो सबसे बड़े हवाई अड्डा संचालक हैं.

एथेनॉल जांच की मांग तेज

नई दिल्ली, 24 जुलाई देशभर में ई-20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच अब पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार और तेल विपणन कंपनियों के सामने एक नई मांग रखी है.

तेल कंपनियों से जांच उपकरण और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग

मिलावटी ई-20 पेट्रोल बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

उनका कहना है कि यदि सरकार मिलावटी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर सख्त कार्रवाई करना चाहती है, तो पहले पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा और गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि पेट्रोल में वास्तव में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिला हुआ है. हाल के दिनों में ई-20 पेट्रोल को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आई हैं. कुछ लोगों का दावा है कि इससे वाहनों के इंजन पर असर पड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि मानकों के अनुरूप तैयार ई-20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है.

भारतीय शिल्प की आत्मा रहे अडिग

नई दिल्ली, 24 जुलाई। वैशाली एस द्वारा भारतीय शिल्पकला का मूल भारतीय ही रहना चाहिए। वैश्विक बनने की आवश्यकता उसकी प्रस्तुति की भाषा को है। मेरे लिए किसी भी परिधान की आत्मा और उसकी अभिव्यक्ति दो बिल्कुल अलग बातें हैं।

आत्मा कभी नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति समय के साथ निरंतर विकसित होती रहनी चाहिए। परिधान की आत्मा में वह सब कुछ शामिल है जो उसे दुनिया में कहीं और दोहराया नहीं जा सकता—हमारी हैंडलूम परंपराएँ,

बुनाई की विशिष्ट तकनीकें, प्राकृतिक रेशे, सदियों से संचित ज्ञान, हमारे कारीगरों का मानवीय स्पर्श और हर शिल्प के पीछे की दार्शनिक सोच। यह केवल हमारी विरासत नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति भी है। यही वह विशेषता है जो केवल भारत के पास है और जिसकी ओर वैश्विक लक्ज़री बाज़ार तेजी से आकर्षित हो रहा है। यह भारतीय वस्त्रों को फिर से उस गौरवपूर्ण स्थान पर स्थापित करने का सुनहरा अवसर है, जहाँ वे सदियों तक रहे हैं। जिस दिन हम इन मूल्यों से समझौता करेंगे, उसी दिन हमारी विशिष्टता समाप्त हो जाएगी। जो बदल सकता है, वह है आज के वैश्विक उपभोक्ता के लिए इस विरासत को प्रस्तुत करने का तरीका। इसका अर्थ है आधुनिक सिल्हूट, समकालीन स्टाइलिंग, उपयोगिता, प्रभावी संवाद और सशक्त कहानी कहना।

2027 के लिए राजनीतिक मोहरे बिछने लगे

युवाओं पर राजनीतिक दलों ने बढ़ाया फोकस

देहरादून. विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उत्तराखंड में राजनीतिक मुहरे बिछने लगी है. सियासत में सत्ता पाने का गुणा भाग भी हो रहा है. उसी लिहाज से आगामी राजनीतिक रणनीति भी तैयार हो रही है.

इसी रणनीति का हिस्सा इस समय सबसे ज्यादा युवा दिखाई दे रहे हैं. ऐसा मौजूदा माहौल और युवाओं की मतदाता के रूप में भूमिका को देखते हुए किया जा रहा है. खास बात यह है कि आगामी चुनाव के नजदीक जाते-जाते युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं पर राजनीतिक दलों का फोकस साफ नजर आ रहा है.

फिलहाल उत्तराखंड युवाओं के मामले में राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बना हुआ है. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी देहरादून में युवाओं से संवाद कर चुके है. जाहिर है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को उनके भविष्य का सपना भी दिखाया है और मौजूदा समय में हो रहे पेपर लीक प्रकरणों पर बात रखकर उनकी भावनाओं को भी छूने की कोशिश की है. खास बात यह है कि राजनीतिक दल उत्तराखंड में युवाओं की ताकत को पहचानते है, वह जानते हैं कि राज्य में युवा मतदाता के रूप में सबसे अहम भूमिका में मौजूद है. आंकड़ों के लिहाज से देखे तो राज्य में फिलहाल मतदाताओं की संख्या 71,33000 के आसपास है. इसमें केवल नए मतदाता यानी 18 से 19 साल की आयु वर्ग वाले युवाओं की बात करें तो इनकी संख्या अकेले 175000 के करीब है.

भाजपा भी मैदान खाली छोड़ने के मूड में नहीं

ऐसा नहीं है कि युवाओं को साधने के लिए केवल कांग्रेस ही जोर दिखा रही हो, सत्ताधारी भाजपा भी मैदान को खाली छोड़ने के मूड में नहीं है और पेपर लीक के मामले आने के बावजूद भी युवाओं को साधने की कोशिश में जुटी हुई है. स्थिति यह है कि एक तरफ राहुल गांधी ने देहरादून में युवाओं के साथ संवाद किया है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने उसी दिन देहरादून जिले में ही युवाओं के साथ संवाद करते हुए यह जताने की कोशिश की है कि युवा आज भी भाजपा के साथ ही हैं. उधर सरकार के युवाओं से जुड़े कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं.

कांग्रेस को चन्नी को साथ रखना होगा

चंडीगढ़. कांग्रेस ने पंजाब का विवाद कुछ हद तक सुलझा लिया है. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी के विरोधी अगर बहुत उछल कूद मचाएंगे या जीत का जश्न मनाएंगे तो कांग्रेस को उसका नुकसान होगा. यह सही है कि चन्नी ने ज्यादा बड़ा दांव खेल दिया था.

वे चाहते थे कि उनको या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए. कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि सीएम रहते चन्नी को सीएम दावेदार पेश करके कांग्रेस ने पिछला चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 18 सीटें मिली थीं. चन्नी खुद अपनी दोनों सीटों पर हार गए थे. उसके बाद वे राज्य छोड़ कर अमेरिका चले गए, जहां से नौ महीने बाद लौटे थे. उसके बाद भी कांग्रेस ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया और वे जीते तो उनको कृषि मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनवाया.

निकाय चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस एक्टिव

जयपुर. राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत चुनावों का ऐलान होते ही प्रदेश की सियासत गरमा गई है. इन चुनावों को सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले का सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान माना जा रहा है.

बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अभी से चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. वहीं, चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और विभिन्न आयोगों में नियुक्तियों का काम भी कुछ महीनों के लिए टलना तय माना जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार नगर निकाय चुनाव सितंबर में दो चरणों में कराए जाएंगे. इसके लिए 22 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी. वहीं पंचायत चुनाव अक्टूबर में 4 चरणों में होंगे और इसकी अधिसूचना 23 सितंबर को जारी की जाएगी. नगर निकाय चुनाव करीब एक साल और पंचायत चुनाव लगभग डेढ़ साल की देरी से हो रहे हैं. राजनीतिक जानकार इन चुनावों को 2028 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं. चुनावी नतीजे यह तय करेंगे कि प्रदेश में किस पार्टी की पकड़ मजबूत है. बीजेपी और कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी), भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी), आम आदमी पार्टी (आप) और एआईएमआईएम भी चुनाव मैदान में उतरकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगी.

सत्ता में होने के कारण बीजेपी को सरकारी योजनाओं और संगठन का फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन अच्छे प्रदर्शन का दबाव भी रहेगा. कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का कहना है कि स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव अलग-अलग होते हैं और हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं.

सभी राजनीतिक दलों की नजर चुनावों पर

राजस्थान में कुल 309 नगर निकाय हैं, जिनमें 10,245 वार्ड शामिल हैं और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा. इसके अलावा प्रदेश की 11,071 ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव होगा. साथ ही 41 जिला परिषद अध्यक्ष और 367 ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए भी मतदान कराया जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. अब सभी राजनीतिक दलों की नजर इन चुनावों पर है, क्योंकि इनके नतीजे प्रदेश की आगामी राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

क्या अखिलेश के बाद सपा का प्लान-बी हैं डिंपल यादव

छवि में किया बदलाव, एक्शन में डिंपल

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी खामोश रहकर पति और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीछे दिखने वाली डिंपल यादव ने पिछले दिनों अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है.

कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने उन्हें एक मौका दिया. इस मौके को वह पूरी तरह से भुनाती नजर आ रही हैं. छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वह प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी दिखीं. बैरिकेटिंग के पास खड़े होकर प्रदर्शन को लीड करती नजर आईं. वहीं, प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद अस्पताल पहुंचकर घायल प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ उनका हालचाल लेती दिखीं. संसद से लेकर जंतर मंतर तक डिंपल यादव के चर्चे हैं. अब इसके पीछे की रणनीति पर भी चर्चा तेज हो गई है. डिंपल यादव को शुरुआती दौर से ही शांत और मंचों पर पीछे की पंक्ति में रहने वाली नेता के तौर पर देखा गया. संसद सत्र के दौरान भी वह अखिलेश यादव के पीछे हमेशा बैठी दिखती रही हैं. हालांकि, छात्र-युवाओं के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान वह फ्रंट फुट पर दिखीं. डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी विरासत को मैनपुरी से आगे बढ़ाया है. अब वह अखिलेश यादव की छवि से इधर आक्रामक महिला लीडर के तौर पर खुद को स्थापित करती दिख रही हैं. उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर की लीडरशिप में जगह दिलाने की कोशिश तेज की है. इस वजह से वह विपक्ष की गोलबंदी और विरोध प्रदर्शनों में हमेशा आगे दिख रही हैं.

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी ज्यादा सक्रिय हैं. पिछले दिनों वे लगातार पिछला दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को धार देने के लिए लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा लेते दिख रहे हैं. माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. इसके जरिए वह अपने पार्टी के कैडर और वोटरों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे. अभी केंद्रीय राजनीति में भी अखिलेश की पार्टी का मुख्य चेहरा हैं. सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी का अन्य कोई मजबूत चेहरा नहीं बन पाया. प्रो. रामगोपाल यादव से लेकर आजम खान तक को केंद्र की राजनीति में सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अखिलेश यादव इसमें उस स्तर पर सफल नहीं हो पाए हैं.

दमदार नेता की है जरूरत

समाजवादी पार्टी को एक ऐसे दमदार चेहरे की जरूरत है, जो संसद में समाजवादी पार्टी का फेस बने. केंद्र की विपक्ष की राजनीति में भी दमदार तरीके से पार्टी का पक्ष रखे. ऐसे में अब अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को आगे कर सेकंड लेवल लीडशिप को मजबूत करने की कवायद तेज की है. माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक अखिलेश यादव लखनऊ में जमे रहेंगे. वह लखनऊ से दिल्ली की पॉलिटिक्स को संभालने की कोशिश करेंगे. वहीं, डिंपल यादव दिल्ली में रहकर पार्टी की राजनीति और रणनीति को स्थापित करने का प्रयास करेंगी.